proposals received I'rom the Stale Government are incomplete and consequently, in such cases. State Governments arc asked to furnish complete information/additional information for disposal.

362 cases were disposed in respect of part C of First Schedule of Mines and Minerals (Regulation and Development) Act during 1997-98. 128 cases in respect of part C of First Schedule of the Act are pending with Central Government as on 1.6.1998. List showing pending cases for approval of Central Government for minerals listed in part A and pan C of First Schedule of Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 arc appended ar Statement I and M respectively. *(See* below)

Statement—I

State	Pending Cases as on 1.6.1998
Ori.ssa	1
Rajasthan	1
TOTAL	2

Statement—II

State	Pending Cases as on 1.6.1998
Andhra Pradesh	19
Bihar	7
Gujarat	14
Himachal Pradesh	4
Karnataka	16
Madhya Pradesh	14
Orissa	26
Rajasthan	15
Tamil Nudu	11
Uttar Pradesh	2
Total	128

इस्पात परिबोजनाओं में पूंजी निवेश

4402. **श्री अनन्तराय देवशकर दवेः** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कपा करेंगे किः

(क) निजी क्षेत्र में स्थापित इस्पात परियाजना में पूंजी निवेश का कुल अंशदान कितना है और इसका राष्ट्रीय और अन्ताराष्ट्रीय निवेश का प्रतिशत कितना-कितना है;

(ख) क्या सरकार ने निजी उपकर्मों में निवेश के लिये कोई विशिष्ट नीति बनाई है जिसके अन्तर्गत वित्तीय संरचना को परिभावित किया जा सके;

(ग) क्या निजी क्षेत्र ने अपनी उत्पादकता क्षमता को वित्तीय निधेश के अनुसार कायम रखा है; और

(घ) प्रत्येक उपक्रम में धारिता का वर्तमान प्रतिशत क्या-क्या है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस)ः (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार जुलाई, 1991 के बाद अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं में 19 इस्पात परियोजनाओं को अनुमोदित और स्वीकृत किया है। इनका कुल निवेश लगभग 25,000 करोड़ रुपये है। इनमें से इकाइयां चालू की गई हैं जिनमें कुल निवेश प्रतिशत 6000 करोड़ रुपए हुआ है। इस निवेश में स्वदेशी और विदेशी पार्टियों की प्रतिशतता के अंशदान से संबंधित जानकारी का केन्दीय रूप से प्रबोधन नहीं किया जाता।

(ख) विद्यामान नीति के अनुसार 74 प्रतिशत तक विदेशी निवेश करने की निर्बाध रूप से अनुमोदित है। इससे अधिक विदेशी समस्या के लिए सराकर का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होता है।

(ग) यह आशा नहीं है कि निजी क्षेत्र तकनीकी आर्थिक रूप से सुदृढ़ हुए बगैर कोई निवेश करेगा।

(घ) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

Irion and Steel Produced by PSUS

4402 SHRl RAMDAS AGARWAL: Wai the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) the quantum of iron, steel and iron alloys produced by Public Sector Undertakings/ Private Sector during the year 1997-98 till date as compared to the corresponding last year (1996-97), plant-wise;

(b) the names of the countries to which iron, steel and iron alloys have been exported till date alongwith quantity/rates of each metal during the above mentioned period indicating foreign exchange earned therefrom; and

(c) the details of said items imported during 1997-98 as compared to 1996-97 indicating the rates, quantities thereof (country-wise) till date?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL & MINES (SHRI RAMESH BAIS):(a) The quantity of pig iron, steel and alloys/stainless steel produced by Public Sector/Private Sector steel plants during 1997-98 as compared to the corresponding period last year (1996-97) plant-wise was as under:--